delivery boys start smoking themselves and accidents do occur. This is a very weak link in the entire chain and we are trying to strengthen it. It is rule that inside the bottling plant whenever anybody is found smoking, he is immediately dismissed from service. This is a very serious offence. For the delivery boys also some such arrangement could be made: we are trying to look into this.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Chairman, Sir, almost every day we read in the newspapers the tragedy of death of housewives due to explosion of gas cylinders. They look almost like bombs planted in the house. Last week three such accidents took place in Madras city alone. So, I would like to know from the Minister whether, whenever such accidents are reported, the Ministry institutes or orders an inquiry to go into the reasons of such accidents and to take steps to prevent such accidents.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: I have already stated that accidents do occur because of leakages and the police takes cognizance of it. They are reported to us also. Hardly any case of burst of cylinder, as is alleged in the news report, has come to our notice.

Tender bid for HBJ pipeline

*3. SHRI SURESH KALMADI:

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what was the tender bid of the Franco-Japanese consortium Spie Capag-NKK which won the bid for the HBJ Pipeline Project;

(b) what is the schedule for the completion of the project; and

(c) whether Government had set up a committee to go into the issue of Aero-derivative turbine or industral gas turbine engines for the HBJ Pipeline project and whether this committee had submitted its report before the bid was announced?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) The quoted price of the revised bid submitted by the constortium led by the Capag of France on 3rd April, 1986 was Rs. 760.48 crores.

(b) The project scheduled to be completed in all respects by July, 1989.

(c) No, Sir. The task force which evaluated the technical bids had gone into this issue. The recommendations of the task force was received and accepted before the award of the contract.

श्री रामानन्द यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह नयी कंपनी को, जापान और फ्रांस की कंपनी को जो ठेका दिया गया है . . . .

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Mobile Telephone System

*4. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently introduced a mobile telephone system in the Capital;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the number of private subscribers who have applied for the mobile telephones so far;

(d) what is the number of subscribers who have actually been provided mobile telephones so far; and

(e) by when the mobile telephones are likely to be provided to the remaining subscribers?

---

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Kalmadi.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir.

(b) Mobile telephone system with a capacity of 100 telephones has been introduced on an experimental basis in Delhi. This service can be availed in Delhi from a mobile telephone installed in the vehicle of the subscriber. Separate tariff has been prescribed for the service.

(c) 295 private subscribers have applied for the mobile telephones as on 17-4-1986.

(d) 51 subscribers have been provided with mobile telephones so far.

(e) Mobile telephones to remaining subcribers will only be provided after additional equipment is procured.

टेलीफोन विभाग में कदाचार

*5. **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली टेलीफोन के गाजियाबाद, शाहदरा पूर्व, 20, 21, लक्ष्मी नगर, दिल्ली गेट तथा ईदगाह टेलीफोन केन्द्रों में पिछले कई वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन लगाने तथा टेलीफोन मीटरों की काल रीडिंग के मामले में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेरा-फेरी को रोकने के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच करवाई है और उसका ब्यौरा क्या है, और यदि कोई जांच नहीं करवाई गई, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की अनियमितताएं विभाग के खासकर वे गिने-चुने अधिकारी करते है जिन्हें एक ही क्षेत्र में लम्बे अर्से तक तैनात किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कोई उच्च स्तरीय जांच करायी है और उन अधिकारियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

बेरोजगार स्नातकों को रसोई गैस के लिए एजेंसियों का आबंटन

*6. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

डा. बापू कालिदास :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 10 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1395 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 232 पेट्रोल पम्पों में से केवल 11 पम्प बेरोजगार स्नातकों को दिए गए और यदि हां, तो इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है ;

(ख) इस बारे में पूरे देश में और विशेषकर बिहार में विद्यमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में तथा दिल्ली में भी बेरोजगार युवकों को रसोई गैस की डीलरशिप देने के मामले में क्या नीति अपनायी है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दिल्ली संघ राज्य में इस समय एम.एस/एच.एस.डी. रिटेल आउटलेटों की कुल मिलाकर संख्या 232 है इसमें उस समय के स्थापित रिटेल आउटलेट भी शामिल है जब बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों (यूजी/यूईजी) के लिए आरक्षण नहीं था । इनमें से 11 रिटेल आउटलेट बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए आई.ओ.सी. की योजना जो वर्ष 1970 और 1971 में चालू थी, के अन्तर्गत दिये गये थे । 1982-83 से अपनाई गई नीति में इस श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है । इसका अनुपालन किया जा रहा है ।

(ख) 1982-83 और 1985-86 के बीच देश में कुल योजित 1914 रिटेल आउटलेटों में से 456 यू.जी/यू.ई.जी. श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए । बिहार के सम्बन्ध में इनकी संख्या क्रमश: 175 और 45 है ।